



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 5 दिसम्बर, 1996/14 अग्रहायण, 1918,

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 5 दिसम्बर, 1996

संख्या 1-65/96-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक,

संख्यांक 32) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सुल्लनार्ज असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1996

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में विवाह के रजिस्ट्रीकरण और इससे सम्बद्ध कजियय अन्य विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सैतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 है। संक्षिप्त नाम,
विस्तार
और
प्रारम्भ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।
- (3) यह उम तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ या विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार" से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;
 - (ख) "विवाह करने" से किसी भी रूप या रीति में विवाह अनुष्ठापित करना या विवाह करना अभिप्रेत है ;
 - (ग) "विवाह का जिला रजिस्ट्रार" से किसी जिला के लिए इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विवाह का जिला रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;
 - (घ) "विवाह" के अन्तर्गत पुनर्विवाह भी है ;
 - (ङ) "विवाह रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन रखा गया विवाह रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;
 - (च) "पुरोहित" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो विवाह अनुष्ठापित करता है ;
 - (छ) "विवाह रजिस्ट्रार" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त विवाह रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;
 - (ज) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संबन्धित अनुसूची अभिप्रेत है।

अध्याय-2

रजिस्ट्रीकरण-स्थापन

विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार। 3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, ऐसे पदनामों से ऐसे अन्य अधिकारी भी, जैसे वह ठीक समझे ऐसे कृत्यों को जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन नियुक्त कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के अधीन, यदि कोई हो, विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में, इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाए गए नियमों और दिये गए आदेशों के निष्पादन के लिए विवाह का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होगा।

(4) विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण की दक्षपद्धति, सुनिश्चित करने के लिए, राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य का समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण करने के लिए, उपयुक्त अनुदेश जारी करके या अन्यथा कदम उठाएगा। राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में, ऐसी रीति से और ऐसे अन्तरालों पर जो विहित किए जाएं, रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

विवाह का जिला रजिस्ट्रार।

4. (1) राज्य सरकार, प्रत्येक राजस्व जिले के लिए, एक विवाह का जिला रजिस्ट्रार और उतने ही विवाह के अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और जो विवाह के सिवाय रजिस्ट्रार के साधारण नियन्त्रण और निदेशन के अधीन रहते हुए विवाह के जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनका निर्वहन करने के लिए विवाह का जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे।

(2) विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार के निदेशन के अधीन रहते हुए, विवाह का जिला रजिस्ट्रार जिले में विवाह के रजिस्ट्रीकरण का अधीक्षण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा जिले में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

विवाह रजिस्ट्रार।

5. (1) राज्य सरकार, तहसील या ताल्लुका या नगर निगम, नगर पालिका या किसी छावनी बोर्ड या अन्य प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए या किसी अन्य क्षेत्र के लिए भी उनमें से दो या अधिक के समुच्चय के लिए एक विवाह रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी नगर निगम या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की दशा में उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन विवाह रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) विवाह का प्रत्येक रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन रखे गए रजिस्ट्रार में उसे दी गई इतलाह की फीस या ईनाम के बिना दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्येक विवाह के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी सतर्कता से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित विशिष्टियों के अभिनिश्चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिए भी कदम उठाएगा।

(3) विवाह के प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया हो।

(4) विवाह का प्रत्येक रजिस्ट्रार, विवाह के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसी तारीख और ऐसे समय में उपस्थित होगा जैसा विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार निदेश दे, और विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगावाएगा जिस पर उसका नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए वह नियुक्त हो उमका, विवाह रजिस्ट्रार तथा उसकी उपस्थिति के समय स्थानीय भाषा में लिखे होंगे।

अध्याय-3

विवाह का रजिस्ट्रीकरण

6. उस तारीख के पश्चात् जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन प्रवर्तन में लाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में किया गया प्रत्येक विवाह इस अधिनियम की धारा 7 में उपबन्धित रीति में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण किया जाना।

7. (1) विवाह के पक्षकार या उनके पिता या संरक्षक, जब उन्होंने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, अनुसूची के प्रस्ताव में एक जापन तैयार और हस्ताक्षरित करेंगे और उक्त जापन को दो प्रतियों में विवाह की तारीख में तीन दिन के भीतर क्षेत्र के विवाह रजिस्ट्रार को परिदत्त करेंगे, या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेंगे :

विवाह का जापन।

परन्तु जहां विवाह, पक्षकार के पिता या संरक्षक की सहमति के बिना किया जाता है, वहां ऐसा पक्षकार और न कि पिता या संरक्षक, इस उप-धारा के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

(2) जापन पुरोहित यदि कोई हो, द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा, और जहां ऐसा विवाह, विवाह अधिकारी के समक्ष अनुष्ठापित किया जाता है तो जापन, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उक्त विवाह अधिकारी द्वारा रखे गए विवाह प्रमाणपत्र पुस्तक में की गई प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियों द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(3) जापन के साथ पांच रुपये की फीस दी जाएगी।

(4) जापन की प्राप्ति पर उसे, उस द्वारा रखे गए रजिस्टर में फाइल करेगा और उसकी द्विप्रतिक प्रतिलिपि मुख्य विवाह रजिस्ट्रार को भेजेगा।

विवाह के जापन का तीस दिन के पश्चात् प्रस्तुत करना।

8. (1) किसी विशिष्ट विवाह के बारे में जापन, दस रुपये से अनधिक ऐसी फीस सहित, जैसी विहित की जाए, धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के पश्चात् विवाह रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जा सकेगा और विवाह रजिस्ट्रार उसे उस द्वारा रखे गए विवाह रजिस्ट्रार में फाइल करेगा तथा उसकी दूसरी प्रतिलिपि मुख्य विवाह रजिस्ट्रार को भी भेजेगा जैसा धारा 7 में उपबन्धित है।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात किसी व्यक्ति, जिम्मे धारा 7 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जानबूझ कर जापन परिदत्त करने या भेजने में चूक या उपेक्षा की है, इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन किसी शास्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी।

(3) कोई विवाह, जिसकी विलम्बित सूचना, नव्वे दिन के पश्चात्, किन्तु इसके होने के एक वर्ष के भीतर, विवाह रजिस्ट्रार को दी जाती है, केवल विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और विहित फीस के संदाय तथा नोटरी पब्लिक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए, अपश्च-पत्र को पेश करने पर, रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(4) कोई विवाह, जिसे इसके होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, केवल प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट द्वारा, विवाह की सत्यता का सत्यापन करने के पश्चात् और विहित फीस के संदाय पर, किए गए आदेश पर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, धारा 11 के अधीन विदेशीय विवाह के रजिस्ट्रीकरण को लागू नहीं होगी।

विवाह के रजिस्ट्रीकरण का स्थान।

9. रजिस्ट्रीकरण उस विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया था या जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह का कोई एक या दोनों पक्षकारों का स्थायी आवास हो, या उसके कार्यालय के बाहर किसी अन्य स्थान पर वगैरें कि इस निमित्त लिखित रूप में कोई आवेदन किया गया हो और उसे विवाह के किसी एक पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो तथा उसके लिए विहित अतिरिक्त फीस संदत्त की गई हो तथा समय अयुक्तियुक्त न हो।

उन क्षेत्रों में किए गए विवाह का, स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण जहां यह अधिनियम लागू नहीं है।

10. (1) किसी भी क्षेत्र में जिसमें इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं उस क्षेत्र में किए गए विवाह के पक्षकार या उनके पिता या संरक्षक जब उन्होंने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, यदि वह ऐसा करना चाहे अनुसूची में दिए गए प्ररूप में जापन तैयार करके उस पर हस्ताक्षर करेगा और उक्त जापन को दो प्रतियों में ऐसे रजिस्ट्रार को भेजेगा या परिदत्त करेगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में, अधिवचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) जापन पुरोहित, यदि कोई हो, द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा और जहां ऐसा विवाह अधिकारी के समक्ष अनुष्ठापित किया गया हो, वहां जापन,

उक्त विवाह अधिकारी द्वारा तत्पक्ष प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रखे विवाह प्रमाण पत्र पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियों में सम्मिलित होगा।

(3) ज्ञापन यदि, विवाह की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर भेजा जाता है या परिदत्त किया जाता है तो इसके साथ पांच रुपये की फीस संलग्न करनी होगी और यदि यह विवाह की तारीख से तीस दिन के अवसान के पश्चात् भेजा जाता है या परिदत्त किया जाता है तो दस रुपये से अनधिक ऐसी फीस जो विहित की गई हो संलग्न की जाएगी।

(4) ऐसे ज्ञापन की प्राप्ति पर, विवाह का रजिस्ट्रार, उसे उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में फाइल करेगा और उसकी दूसरी प्रति, धारा 7 में यथा-उपस्थित के अनुसार विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार को भेजेगा।

11. (1) जहां—

- (क) विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि पक्षकारों के मध्य विवाह जिसमें एक पक्षकार भारत का नागरिक हो, विदेश में उस देश की विधि के अनुसार सम्यक् रूप से अनुष्ठापित किया गया हो; और
- (ख) विवाह का पक्षकार, जिस देश में विवाह अनुष्ठापित किया है उस देश में भारतीय कौंसल से प्रमाण-पत्र सहित अनुसूची में दर्शाए गए प्ररूप में, ज्ञापन प्रस्तुत करना है कि विवाह विधिमान्य है और सम्यक् रूप से अनुष्ठापित किया गया है, और विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार को सूचित करना है,

विदेश में
किए गए
विवाह का
रजिस्ट्री-
करण।

कि वह (दोनों में से कोई पक्षकार) विवाह को रजिस्ट्रीकृत करवाना चाहता है, वहां विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार विहित शर्तों के मंदाय पर विवाह को रजिस्टर कर सकेगा।

- (2) इस धारा के अधीन कोई विवाह तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के समय वह विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 की धारा 4 में अधिकथित शर्तों का समाधान नहीं करेगा।

(3) मुख्य विवाह रजिस्ट्रार, कारणों को अभिलिखित करते हुए, इस अधिनियम के अधीन इस आधार पर विवाह का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर सकेगा कि उस की राय में विवाह अन्तर्राष्ट्रीय विधि या अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य से असंगत है।

(4) जहां मुख्य विवाह रजिस्ट्रार, आवेदन को स्वीकार करता है, वहां वह विवाह रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(5) जहां किसी विवाह का कोई पक्षकार भारत से बाहर है और उसमें बसने की दृष्टि से वह भारत वापस आता है, वहां वह, भारत में अपने आने की तारीख से साठ दिन के भीतर, किसी भी समय, इस अधिनियम के अधीन विवाह को उसी रीति में रजिस्ट्रीकृत करेगा मानो विवाह भारत में अनुष्ठापित किया गया हो और धारा 8 के उपबन्ध, उक्त साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसे विवाह को लागू होंगे।

अरजिस्ट्री- 12. उन क्षेत्रों में किया गया कोई विवाह जिनको यह अधिनियम लागू होता
करण से है, एकमात्र इस तथ्य के कारण अविधिमानी नहीं समझा जाएगा कि यह इस
विवाह का अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया था या ज्ञापन विवाह रजिस्ट्रार को
अविधिमानी परित्यक्त या भेजा नहीं गया था अथवा ऐसा ज्ञापन तृटिपूर्ण, अनियमित या
न होना। गलत था।

अध्याय-4

रजिस्टर और अभिलेख का रखा जाना तथा उसकी संशुद्धियां

विहित प्ररूप में रजिस्टर रखना। 13. (1) प्रत्येक विवाह रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए जिसके सम्बन्ध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, विहित प्ररूप में एक विवाह रजिस्टर रखेगा।

(2) मुख्य विवाह रजिस्ट्रार, विवाह की प्रविष्टियां करने के लिए, ऐसे प्ररूप और अनुदेशों के अनुसार जो, समय-समय पर विहित किए जाएं, पर्याप्त संख्या में रजिस्टर मुद्रित और उनकी आपूर्ति करवाएगा; और ऐसे प्ररूपों की एक प्रतिलिपि स्थानीय भाषा में किसी सहजदृश्य स्थान या कार्यालय के बाहरी द्वार पर चिपकाई जाएगी।

विवाह रजिस्टर में प्रविष्टि की संशुद्धि या रद्दकरण। 14. यदि विवाह रजिस्ट्रार के सभाधानप्रद यह पाया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन रखे गए किसी रजिस्टर में विवाह की कोई प्रविष्टि, प्ररूप में सार में गलत है या कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गई है, तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा उस शर्त की बाबत बनाए जाएं जिस पर और परिस्थितियां जिन में ऐसी प्रविष्टियां संशुद्ध या रद्द की जा सकेंगी, मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किए बिना, सीमांत में उपयुक्त प्रविष्टि करके प्रविष्टि की गलती को संशुद्ध या रद्द कर सकेगा।

विवाह रजिस्टर की तलाशी। 15. कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्वधीन जिसके अन्तर्गत फीस और डाक प्रभार सम्बन्धी नियम भी हैं,—

(क) विवाह के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की विवाह रजिस्ट्रार द्वारा तलाशी करवा सकेगा; और

(ख) किसी विवाह सम्बन्धी ऐसे रजिस्टर से उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।

1872 का 1 • (2) इस धारा के अधीन दिए गए सभी उद्धरण रजिस्ट्रार या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 76 में यथा उपबन्धित ऐसे उद्धरण देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

अध्याय-5

शास्ति

16. कोई व्यक्ति जो—

(i) धारा 7 के अधीन यथा अपेक्षित जापन को जानबूझ कर परिदेन करना या भेजना, छोड़ देता है या उपेक्षा करता है ; या

(ii) ऐसे जापन में कोई कथन करता है जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है और जिसका वह जान रखता है या उसके पान मिथ्या होने का कारण है,

दोषसिद्धि पर जुर्माने में, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 7 के उपबन्धों के अनुपालन में उपेक्षा करने या जापन में मिथ्या कथन करने के लिए शास्ति।

17. विवाह का कोई रजिस्ट्रार, जो धारा 7 के अनुसरण में जापन दायर करने में असफल रहता है, दोषसिद्धि पर, कठोर कारावास में, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने में जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा या दोनों में दण्डनीय होगा।

जापन दायर करने में असफल रहने पर शास्ति।

18. विवाह रजिस्ट्रार या उसके किसी भाग को छिपाने, नष्ट करने या बेईमानी या कपट से परिवर्तित करने वाला कोई व्यक्ति दोषसिद्धि पर कारावास में, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

विवाह रजिस्ट्रार को गोपनीय रखने, नष्ट करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए शास्ति।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

19. विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार, विवाह के जिला रजिस्ट्रार, विवाह के अपर जिला रजिस्ट्रार, विवाह के रजिस्ट्रार, और इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी जब इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, वे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होंगे।

रजिस्ट्रारों का लोक सेवक होना।

20. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आणियत किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

इस अधिनियम के अधीन कार्यरत व्यक्तियों का परित्राण।

सरकार की 21. सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय पूर्व मंजूरी। किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

नियम बनाने की 22. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित के राज्य सरकार लिए नियम बना सकेगी—
की शक्ति।

- (क) विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार, विवाह के जिला रजिस्ट्रार, विवाह के रजिस्ट्रार और सहायता देने के लिए नियुक्त अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें, कर्तव्य और शक्तियां;
- (ख) प्ररूप और रीति जिसमें इस अधिनियम द्वारा या के अधीन रजिस्टर या अभिलेख रखे जाने अपेक्षित हैं;
- (ग) अभिरक्षा जिसमें रजिस्टर और अभिलेख रखे जाने हैं और ऐसे रजिस्ट्रारों और अभिलेखों का परिरक्षण;
- (घ) इस अधिनियम के अधीन संदत्त की जाने वाली फीसें; और
- (ङ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व सहमत हो जाए कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कनिष्ठ विधियों में उपबन्धों का अल्पीकरण में न होना।	23. इस अधिनियम के उपबन्ध, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 और विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे और अल्पीकरण में नहीं होंगे।	1954 का 43 1872 का 15 1936 का 3 1969 का 33
---	---	---

अनुसूची

प्ररूप

(धारा 7 देखें)

विवाह का ज्ञापन

1. विवाह की तारीख।
2. विवाह का स्थान (स्थान पता लगाने के लिए पर्याप्त विशिष्टियों सहित)।

3. (क) वर का पूरा नाम ।
 (ख) उसकी आयु ।
 (ग) आवास का सामान्य स्थान ।
 (घ) पता ।
 (ङ) विवाह के समय वर की हैसियत (क्या अविवाहित/विधुर/विच्छिन्न विवाह/विवाहित, यदि ऐसा है, किननी पत्नियां जीवित हैं) ।
 (च) तारीख सहित, वर के हस्ताक्षर ।
4. (क) वधू का पूरा नाम ।
 (ख) उसकी आयु ।
 (ग) आवास का सामान्य स्थान ।
 (घ) पता ।
 (ङ) विवाह के समय वधू की हैसियत (क्या अविवाहित/विधवा/विच्छिन्न विवाह/विवाहित, यदि ऐसा है, पति जीवित हैं) ।
 (च) तारीख सहित, वधू के हस्ताक्षर ।
5. (क) वर के पिता या संरक्षक का पूरा नाम ।
 (ख) उसकी आयु ।
 (ग) आवास का सामान्य स्थान ।
 (घ) पता ।
 (ङ) तारीख सहित, वर के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर ।
6. (क) वधू के पिता या संरक्षक का पूरा नाम ।
 (ख) उसकी आयु ।
 (ग) आवास का सामान्य स्थान ।
 (घ) पता ।
 (ङ) तारीख सहित, वधू के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर ।
7. (क) पुरोहित का पूरा नाम ।
 (ख) उसकी आयु ।
 (ग) आवास का सामान्य स्थान ।
 (घ) पता ।
 (ङ) तारीख सहित, पुरोहित के हस्ताक्षर ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विवाह का रिवाज एक अपरिहार्य सामाजिक आवश्यकता है। यह बचपन से बुढ़ापे तक सभी घरेलू आराम की व्यवस्था करता है और हमारे जीवन की प्रत्येक समस्याओं का निपटारा करता है। अतीत में, विरले मामलों में ही ऐसा होता था कि विवाह के कार्य का सम्पन्न होने से इन्कार किया जाता था। अब सामाजिक और आर्थिक विकास के कारण आधुनिक समाज में अत्याधिक परिवर्तन के साथ, वैध विवाह के कार्य को साधारणतया विवादित किया जाता है और इसी कारण से विवाह के कुछ सबूतों का उपबन्ध करने के लिए विवाह का रजिस्ट्रीकरण करने के उपबन्धों का आलंबन लिया गया है। वर्तमानतः विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध एकरूप और आबद्धकर नहीं हैं। इसलिए यह समय की आवश्यकता है कि विवाह के आवश्यक रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध बनाए जाएं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

विद्या धर,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:

5 दिसम्बर, 1996.

वित्तीय ज्ञापन

खण्ड 3, 4 और 5 विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के कार्यान्वयन का प्रबन्ध करने के विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए उपबन्ध करते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष में से मुबलिन 9 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

खण्ड 22, विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए बनाए जाएंगे और विधान सभा के समक्ष रखे जाने हैं। यह प्रत्यायोजन आवश्यक और मामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(कल्याण विभाग नस्ति संख्या डब्ल्यू एल एफ-ए (3) 6/96)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1996 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

Bill No. 32 of 1996

THE HIMACHAL PRADESH REGISTRATION OF MARRIAGES
BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A
BILL

to provide for registration of marriages and for certain other matters connected therewith.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of Republic of India, as follow:—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996. Short title, extent and commencement.
- (2) It extends to the whole of the Himachal Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,— Definitions.

- (a) "Chief Registrar of Marriages" means the Chief Registrar of Marriages appointed by the State Government under section 3 of this Act;
- (b) "to contract a marriage" means to solemnize or enter into a marriage in any form or manner;
- (c) "District Registrar of Marriages" means the District Registrar of Marriages appointed by the State Government for a district under section 6 of this Act;
- (d) "marriage" includes re-marriage;
- (e) "marriage register" means a register of marriages maintained under this Act;
- (f) "Priest" means any person who solemnises a marriage;
- (g) "Registrar of Marriages" means a Registrar of Marriages appointed by the State Government under section 5 of this Act;
- (h) "Schedule" means the Schedule to this Act.

CHAPTER-II

REGISTRATION-ESTABLISHMENT

3. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a Chief Registrar of Marriages for the State. Chief Registrar of marriages.
- (2) The State Government may also appoint such other officers with such

designations as it thinks fit for the purpose of discharging under the superintendence and direction of the Chief Registrar of Marriages, such of his functions as he may, from time to time, authorise them to discharge.

(3) The Chief Registrar of Marriages shall be the Chief Executive Authority in the State for carrying into execution the provisions of this Act and the rules and orders made thereunder subject to the directions, if any, given by the State Government.

(4) The Chief Registrar of Marriages shall take steps, by the issue of suitable instructions or otherwise, to co-ordinate, unify and supervise the work of registration in the State for securing an efficient system of registration and shall prepare and submit to the State Government, in such manner and at such intervals as may be prescribed, a report on the working of this Act in the State.

District
Registrars
of
Marriages.

4. (1) The State Government may appoint a District Registrar of Marriages for each revenue District and such number of Additional District Registrars of Marriages, as it thinks fit, who shall, subject to the general control and direction of the District Registrar of Marriages, discharge such functions of the District Registrar of Marriages, as the District Registrar of Marriages may from time to time authorise them to discharge.

(2) The District Registrar of Marriages shall superintend, subject to the direction of the Chief Registrar of Marriages, the registration of marriages and shall be responsible for carrying into execution in the District the provisions of this Act and the orders of the Chief Registrar of Marriages issued from time to time for the purposes of this Act.

Registrar
of
Marriages.

5. (1) The State Government may appoint a Registrar of Marriages for each local area comprising the area within the jurisdiction of a tehsil or taluka or a municipal corporation, municipality or a cantonment board or any other local authority or a combination of any two or more of them :

Provided that the State Government may appoint in the case of municipal corporation, municipality or other local authority, any officer or other employees thereof as a Registrar of Marriages under this Act.

(2) Every Registrar of Marriages shall, without fee or reward, enter in the Marriage Register maintained under this Act and shall also take steps to inform himself carefully of every marriage, which takes place in his jurisdiction and to ascertain and register the particulars required to be registered.

(3) Every Registrar of Marriages shall have an office in the local area for which he is appointed.

(4) Every Registrar shall attend his office for the purpose of registering marriages on such days and at such hours as the Chief Registrar of Marriages may direct and shall cause to be placed in conspicuous place on or near the out door of the office of the Registrar of Marriages a board bearing, in the local language, his name with the addition of Registrar of Marriages for the local area for which he is appointed, and the days and hours of his attendance.

CHAPTER-III

REGISTRATION OF MARRIAGES

6. After the date on which the provisions of this Act have been brought into force in any area under sub-section (3) of section 1, every marriage contracted in Himachal Pradesh shall be registered in the manner provided in section 7 of this Act.

Every marriage to be registered.

7. (1) The parties to a marriage or their fathers or guardians when they shall not have completed the age of 21 years, shall prepare and sign a memorandum in the form in the Schedule and shall deliver or send by registered post the said memorandum in duplicate to the Registrar of Marriages of the area, within a period of 30 days from the date of the marriage :

Memorandum of marriage.

Provided that where the marriage is contracted without the consent of the father or guardian of a party, such party and not the father or guardian shall comply with the provisions of this sub-section.

(2) The memorandum shall also be signed by the priest, if any and where such marriages is solemnised before a Marriage Officer, the memorandum shall be supported by certified copies of the entries made in the Marriage Certificate Book being maintained by the said Marriage Officer under any other enactment for the time being in force.

(3) The memorandum shall be accompanied by a fee of rupees five.

(4) On receipt of the memorandum, the Registrar of Marriages shall file the same in the marriage register maintained by him and shall send the duplicate copy thereof to the Chief Registrar of Marriages.

8. (1) A memorandum, accompanied by a fee, not exceeding rupees ten as may be prescribed, regarding any particular marriage may be submitted to the Registrar of Marriages after the expiry of period of 30 days specified under sub-section (1) of section 7 and the Registrar of Marriages shall file the same in the marriage register maintained by him and shall also send the duplicate copy thereof to the Chief Registrar of Marriages as provided in section 7.

Memorandum of marriages submitted after 30 days.

(2) Nothing in sub-section (1) shall affect the liability of any person who has wilfully omitted or neglected to deliver or send the memorandum within the period specified in sub-section (1) of section 7 to any penalty under section 16 of this Act.

(3) Any marriage of which delayed information is given to the Registrar of Marriages after ninety days but within one year of its occurrence shall be registered only with the written permission of the prescribed authority and on payment of prescribed fee and production of an affidavit made before a Notary Public or any other officer authorised by the State Government in this behalf.

(4) Any marriage which has not been registered within one year of its occurrence, shall be registered only on an order made by a Magistrate of the First Class after verifying the correctness of marriage and on payment of the prescribed fee :

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to the registration of a foreign marriage under section 11.

Places of
registration
of
marriages.

9. The registration shall be effected in the office of the Registrar of Marriages within whose jurisdiction the marriage was solemnised or within whose jurisdiction, either or both parties to the marriage have their permanent place of residence or at any place outside his office provided there is any application in writing in this behalf and signed by either of the parties to the marriage and the additional fee prescribed therefor is paid and the hour is not unreasonable.

Voluntary
registra-
tion of
marriages
contracted
in areas in
which the
Act is not
applicable.

10. (1) In any area in which the provisions of this Act are not in force, the parties to a marriage contracted in that area, or that their fathers or guardians when they shall not have completed the age of 21 years, may if they so desire, prepare and sign a memorandum in the form in the Schedule and deliver or send by registered post the said memorandum in duplicate to such Registrar of Marriages, as the State Government may, from time to time by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

(2) The memorandum shall also be signed by the priest, if any, and where such marriage is solemnised before a Marriage Officer, the memorandum shall be supported by certified copies of entries made in the Marriage Certificate Book being maintained by the said Marriage Officer under any other enactment for the time being in force.

(3) The memorandum shall be accompanied by a fee of rupees five if it is sent or delivered within a period of 30 days from the date of marriage and a fee, not exceeding rupees ten, as may be prescribed, if it is sent or delivered after the expiry of 30 days from the date of marriage.

(4) On receipt of any such memorandum, the Registrar of Marriages shall file the same in the Marriage Register maintained by him and shall send the duplicate copy thereof to the Chief Registrar of Marriages as provided in section 7.

Registra-
tion of
foreign
marriages.

11. (1) Where,—

- (a) the Chief Registrar of Marriages is satisfied that a marriage has been duly solemnised in a foreign country in accordance with the law of that country between the parties of whom one at least was a citizen of India; and
- (b) a party to the marriage submits a memorandum in the form given in the Schedule, along with a certificate from the Indian Consulate, in the country where marriage has been solemnised, that the marriage is valid and has been duly solemnised, and informs the Chief Registrar of Marriages,

that he or she desires the marriage to be registered, the Chief Registrar of Marriages may upon payment of prescribed fee, register the marriage.

(2) No marriage shall be registered under this section unless at the time of registration it satisfies the conditions laid down in section 4 of the Foreign Marriage Act, 1969.

(3) The Chief Registrar of Marriages may, for reasons to be recorded in writing, refuse to register a marriage under this Act on the ground that in his opinion the marriage is inconsistent with international law or the comity of nations.

(4) Where the Chief Registrar of Marriages accepts the application, he shall, cause the marriage to be registered.

(5) Where a party to a marriage happens to be outside India and he returns to India with a view to settling therein, he may, at any time within 60 days from the date of their arrival in India, get the marriage registered under this Act in the same manner as if the marriage has been solemnised in India and the provisions of section 8 shall apply to such a marriage after the expiry of the said period of 60 days.

12. No marriage contracted in the areas to which this Act applies shall be deemed to be invalid solely by reason of the fact that it was not registered under this Act or that the memorandum was not delivered or sent to the Registrar of Marriages or that such memorandum was defective, irregular or incorrect.

Non-registration not to invalidate marriages.

CHAPTER-IV

MAINTENANCE OF REGISTERS AND RECORDS AND CORRECTIONS THEREOF

13. (1) Every Registrar of Marriages shall keep in the prescribed form a register of marriages for the registration area or any part thereof in relation to which he exercises jurisdiction.

Maintenance of registers in the prescribed forms.

(2) The Chief Registrar of Marriages shall cause to be printed and supplied a sufficient number of register books for making entries of marriages according to such forms and instructions as may, from time to time, be prescribed; and a copy of such forms in the local language shall be posted in some conspicuous place or near the outer door of the office.

14. If it is found to the satisfaction of the Registrar of Marriages that any entry of a marriage in any register kept by him under this Act is erroneous in form or substance, or has been fraudulently or improperly made, he may subject to such rules as may be made by the State Government with respect to the condition on which and the circumstances in which such entries may be corrected or cancelled, correct the error or cancel the entry by suitable entry in the margin, without any alteration of the original entry, and shall sign the marginal entry and thereto add the date of the correction or cancellation.

Correction or cancellation of entry in the marriage register.

15. (1) Subject to any rules made in this behalf by the State Government including rules relating to the payment of fees and postal charges, any person may—

Search of marriage registers.

(a) cause a search to be made by the Registrar of Marriages for any entry in a register of marriages; and

(b) obtain an extract from such register relating to any marriage.

- 1 of 1872 (2) All extracts given under this section shall be certified by the Registrar or any other officer authorised by the State Government to give such extracts as provided in section 76 of the Indian Evidence Act, 1872 and shall be admissible in evidence for the purposes of proving the marriage to which it relates.

CHAPTER-V

PENALTIES

Penalty for neglecting to comply with the provisions of section 7 or making any false statement in the memorandum.

16. Any person who —

- (i) wilfully omits or neglects to deliver or send memorandum as required by section 7 ; or
- (ii) makes any statement in such memorandum which is false in material particular, and which he knows or has reason to believe to be false,

shall on conviction, be punished with fine which may extend to two hundred rupees.

Penalty for failing to file memorandum.

17. Any Registrar of Marriages, who fails to file the memorandum pursuant to section 7 shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

Penalty for secreting, destroying or altering marriage register.

18. Any person secreting, destroying, or dishonestly or fraudulently altering the marriage register or any part thereof shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

Registrars to be public servants.

19. The Chief Registrar of Marriages, District Registrars of Marriages, Additional District Registrars of Marriages, Registrars of Marriages and other officers appointed under this Act, shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Indemnity to persons acting under this Act.

20. No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Previous sanction of the Government.

21. No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted except with the previous sanction of the State Government.

Power of State Government to make rules.

22. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act—

- (a) the terms and conditions of appointment; and duties and powers of the Chief Registrar of Marriages, District Registrars of Marriages, Registrars of Marriages, and other officers and staff appointed to assist them;
- (b) the forms and manner in which registers or records, required to be kept by or under this Act, shall be maintained;
- (c) the custody in which the registers and records are to be kept and the preservation of such registers and records;
- (d) the fees to be paid under this Act; and
- (e) any other matter which is to be, or may be, prescribed by the State Government under this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the sessions or the successive sessions aforesaid, the Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rules should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

23. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of the Special Marriage Act, 1954, the Indian Christian Marriage Act, 1872, the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 and the Foreign Marriage Act, 1969.

Provisions
not to be
derogatory
to certain
laws.

43 of 1954
15 of 1872
3 of 1936
33 of 1969

THE SCHEDULE

FORM

(See section 7)

MEMORANDUM OF MARRIAGE

1. Date of marriage.
2. Place of marriage (with sufficient particulars to locate the place).
3.
 - (a) Full name of the bridegroom.
 - (b) His age.
 - (c) Usual place of residence.
 - (d) Address.
 - (e) Status of the bridegroom at the time of marriage (whether unmarried/widower/divorced/married, if so, how many wives are alive).
 - (f) Signatures of the bridegroom, with date.
4.
 - (a) Full name of the bride.
 - (b) Her age.
 - (c) Usual place of residence.
 - (d) Address.
 - (e) Status of the bride at the time of marriage (whether un-married/widow/divorced/married, if so, husband is alive).
 - (f) Signatures of the bride, with date.
5.
 - (a) Full name of the father or guardian of the bridegroom,
 - (b) His age.
 - (c) Usual place of residence.
 - (d) Address.
 - (e) Signature of the father or guardian of the bridegroom, with date.
6.
 - (a) Full name of the father or guardian of the bride.
 - (b) His age.
 - (c) Usual place of residence.
 - (d) Address.
 - (e) Signature of the father or guardian of the bride, with date.
7.
 - (a) Full name of the priest.
 - (b) His age.
 - (c) Usual place of residence.
 - (d) Address.
 - (e) Signatures of the priest, with date.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The institution of marriage is an unavoidable social need. It provides every domestic comforts from infancy to old age and deals with problems in every walk of our life. It is source of important legal rights and obligations. In the past it was in very rare cases that factum of marriage was denied. Now with the sea change in the modern society on account of social and economic development, the factum of a valid marriage is generally disputed and that is why recourse has been taken to the provisions for registration of marriages to provide some proof of marriages. Presently the provisions for the registration of marriages are not uniformed and compulsory. It has, therefore, become the need of the day to provide for compulsory registration of marriages.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIDYA DHAR,
Minister-in-charge.

SHRIMLA

The 5th December, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 3, 4 and 5 make provisions for the appointment of various Officers to handle the implementation of the provisions contained in the Bill. It is estimated that the provisions of the Bill when enacted will involve an extra recurring expenditure out of the State exchequer to the tune of rupees 9 lakhs per annum.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 22 empowers the State Government to make rules for carrying out the provisions of the Bill. The rules are to be made subject to the condition of previous publication and are to be laid before the State Legislature. This delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Welfare Department file No. WLF-A(3)6/96]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of Registration of Marriages Bill, 1996, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, its introduction and consideration in the State Legislative Assembly.